Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन

डॉ. जी. एल. खांगोडे* शिवानी जायसवाल**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान में एमएसएमई क्षेत्र एक अत्यधिक गतिशील कारक साबित हुआ है। चूंकि एमएसएमई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और निर्माण करते हैं, इसलिए उन्होंने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। मध्य प्रदेश (एमपी) नामक राज्य भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और 72 मिलियन से ज़्यादा निवासियों के साथ यह पाँचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और देश का औद्योगिक केंद्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश सरकार इन पहलुओं को पहचानती है और राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती है। इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी राज्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध पत्र में, मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के लिए डेटा एकत्र करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी – एमएसएमई, रोजगार के अवसर, विकास और वृद्धि, चुनौतियां।

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वे संस्थाएं हैं, जो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के अनुसार, उद्यमों को दो प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है – विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। यह वस्तुओं और वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में संलग्न है तथा रोजगार के अवसर पैदा करता है, तथा भारत के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है।

एमएसएमई मंत्रालय देश भर में एमएसएमई के लिए ऋण और वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन सहायता, तकनीकी और गुणवत्त उन्नयन और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन में एमएसएमई के प्रमुख योगदान के कारण, इस अध्ययन में एमएसएमई की वृद्धि और विकास की वर्तमान स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है और विकास की यात्रा में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी अध्ययन किया गया है।

मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से पाँचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इसमें सभी भौगोलिक लाभ हैं, जिसके कारण उद्योगपतियों द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से सभी लाभ होने के बावजूद, राज्य में एमएसएमई का पूरी क्षमता तक विकास नहीं हो पाया है। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के सामने अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं।

इस प्रकार, इस पत्र में, हमने मध्य प्रदेश राज्य में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। यह डेटा के द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जो विभिन्न लेखों, प्रकाशित पत्रिकाओं और रिपोर्टों से एकत्र किए गए हैं।

साहित्य की समीक्षा :

दीपाली सलूजा (2012) ने भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई की भूमिका के बारे में विश्लेषण किया है। इस अध्ययन से पता चला है, कि – एमएसएमई उद्यमशीलता के विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। वे अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार में गहराई भी प्रदान करते हैं। वर्तमान स्थिति में एमएसएमई देश में रोजगार के सबसे बड़े जनरेटर हैं। शोधकर्ता ने सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहित करने वाले हाल के बाजार सुधारों ने देश में उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और इससे कई तरह के आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।

प्रियदर्शिनी ज़ंजुर्ने (2018) ने भारत में एमएसएमई की वृद्धि और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है, कि – अनुमानित बाजार औद्योगिक उत्पादन का लगभग 45%, देश के स्थानीय निर्यात का 40%, औद्योगिक इकाइयों का 45%, 42% मिलियन रोजगार और 8000 से अधिक उत्पादों की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

पूजा खत्री (2019) ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों का अध्ययन किया है और इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है, कि – वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, संचालन और निर्यात क्षमता की समस्याओं से संबंधित विभिन्न पहलू द्वितीयक डेटा पर आधारित हैं।

कार्यशील पूंजी की जरूरत, परामर्श सहायता की कमी, जटिल दस्तावेजीकरण, नवीनतम तकनीकी कौशल की कमी, प्रेरणा की कमी, सूचना का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, जटिल कानून आदि ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका अध्ययन किया गया। इसने कुछ ऐसी नीतियों को भी दिखाया जो ऐसे मुद्दों को हल करने का सुझाव देती हैं जो एमएसएमई इकाइयों की विकास क्षमता में बाधा डालती हैं।

डॉ. डीके नेमा एट अल. (2021) ने मध्य प्रदेश में एमएसएमई की समस्याओं और संभावनाओं का विश्लेषण किया है और दिखाया है, कि – कार्यशील पूंजी और पूंजी निवेश के लिए वित्त की कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, जिसके बाद बुनियादी ढांचे की कमी थी। क्लस्टर विकास कार्यक्रमों और क्लस्टर विकास और औद्योगिक क्षेत्र विकास के साथ एमएसएमई की संभावनाएं अधिक हैं और मेक इन इंडिया योजना एमएसएमई को अधिक अवसर प्रदान करके उनके विकास को सुनिश्चित करेगी। इस अध्ययन से पता चला है कि नीति निर्माण में इन समस्याओं और संभावनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

उद्देश्य – अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संभावनाओं और समस्याओं का पता लगाना है, इसलिए इस अध्ययन के लिए दो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं –

1. मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

अनुसंधान क्रियाविधि – यह शोध द्वितीयक समंक पर आधारित है, जो अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लेखों, प्रकाशित साहित्य, पत्रिकाओं और सर्वेक्षण से एकत्र किए गए हैं। इसके अलावा, हमने विषय वस्तु के बारे में गहराई से जानने के लिए एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार किया है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक प्रकाशित की जाती है।

विश्लेषण तथा व्याख्या :–

तालिका क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या – तालिका 1 में 2017–22 के दौरान मध्य प्रदेश में पंजीकृत एमएसएमई और इन एमएसएमई द्वारा दिए गए रोजगार का विवरण दिखाया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2017–18 की तुलना में एमएसएमई के पंजीकरण में 44% की वृद्धि और रोजगार में 72.55% की वृद्धि हुई है। उसके बाद वर्ष 2019–20 में 2018–19 की तुलना में एमएसएमई के पंजीकरण में –3.06% की गिरावट और रोजगार में – 3.51% की गिरावट आई है। उसके बाद 2020–21 में एमएसएमई के पंजीकरण में –35.22% की गिरावट आई है, लेकिन 2021–22 के दौरान रोजगार में 50.88% की वृद्धि हुई है। उसके बाद वर्ष 2021–22 में पंजीकरण में 31.91% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2020–21 की तुलना में एमएसएमई में रोजगार में –6.12% की गिरावट आई है।

चुनौतियां – प्रकाशित शोध पत्रों, पत्रिकाओं, लेखों और रिपोर्टों आदि जैसे द्वितीयक आंकड़ों की मदद से हमने पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का पता लगाया है:–

1. पूंजी निवेश में कार्यशील पूंजी के लिए वित्त की कमी
2. विपणन अवसरों और सहायता का अभाव
3. कुशल श्रम की अनुपलब्धता
4. मजबूत बुनियादी ढांचे का अभाव
5. नवीनतम तकनीकी कौशल का अभाव
6. प्रेरणा की कमी, जानकारी का अभाव

आगे के शोध के लिए सीमाएँ और कार्यक्षेत्र – यह अध्ययन केवल द्वितीयक आंकड़ों और रिपोर्टों तथा पिछले साहित्य पर आधारित है, जिनका उपयोग मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। कुछ एमएसएमई के प्राथमिक आंकड़ों के उपयोग से एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की अधिक यथार्थवादी समझ मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और अधिक यथार्थवादी आंकड़े एकत्र करने के लिए एमएसएमई के नमूना सर्वेक्षण के माधयम से आगे का अध्ययन किया जा सकता है।

निष्कर्ष – जैसा कि पहले बताया गया है, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देश भर में 12 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को रोज़गार देते हैं। एमएसएमई को व्यापक रूप से आर्थिक विकास का स्रोत और ज़्यादा न्यायसंगत विकास हासिल करने का एक तरीका माना जाता है। एमपी की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई के पंजीकरण में गिरावट आई है, लेकिन दूसरी ओर, वर्ष 2019–20 में रोजगार में वृद्धि हुई है। एमएसएमई के नए खुलने के कारण, मौजूदा एमएसएमई बाजार की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के अवसर का लाभ उठाते हैं, ताकि वे अधिक रोजगार पैदा कर सकें। यह इस वर्ष के दौरान रोजगार की संख्या में विस्तार का एक कारण हो सकता है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं, कि – एमएसएमई के पंजीकरण और रोजगार में वृद्धि में कुछ चुनौतियां और बाधाएं हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. At el, डी.एस. (2018) भारतीय एमएसएमई की समस्याएं और संभावनाएं: एक साहित्य समीक्षा (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस)
2. Et.al, डी.वी. (2020) आत्मनिर्भर भारत का विजन, एमएसएमई की भूमिका
3. गडे, एस (2018) एमएसएमई आर्थिक विकास में भूमिका – भारत के भावी भविष्य पर एक अध्ययन (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स)
4. खत्री, पी. (2019) भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों का एक अध्ययन (आईक्यूएसआर–जेबीएम, 21(2), 5–13)
5. https://mpmsme.gov.in/website/statistics-2
6. https://mpmsme.gov.in/website/home

तालिका क्रमांक 1: मध्य प्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं रोजगार (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की स्थिति)

क्र.	वर्ष	पंजीकृत MSME	प्रतिशत	कमी/ वृद्धि दर	रोजगार	प्रतिशत	कमी/ वृद्धि दर
1.	2017-18	206142	16.82	आधार वर्ष	596990	10.80	आधार वर्ष
2.	2018-19	297595	24.28	+44%	1030084	18.63	+72.55%
3.	2019-20	288479	23.54	-3.06%	993876	17.98	-3.51%
4.	2020-21	186876	15.25	-35.22%	1499642	27.13	+50.89%
5.	2021-22	246513	20.11	+31.91%	1407858	25.46	+6.12%
	कुल	**1225605**	**100**		**5528450**	**100**	

स्त्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

****